



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 19, 1999/श्रावण 28, 1921

No. 68]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1999/SRAVANA 28, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1999

फा. सं.-11/5/86-ईपी (एपी-IV).—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 है।

(2) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (i) “अधिनियम” से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;
- (ii) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (iii) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (iv) “समिति” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई समिति अभिप्रेत है;
- (v) “सक्षम प्राधिकारी” से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (vi) “निदेशक” से प्राधिकरण का निदेशक अभिप्रेत है;
- (vii) “कर्मचारी” से उसके वेतनमान या प्रास्थिति को ध्यान में लाए बिना प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (viii) “सरकार जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार आती है” से भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय या किसी अन्य संदर्भ में समुचित मंत्रालय अभिप्रेत है;
- (ix) “सदस्य” से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी आता है;
- (x) “रजिस्टर” से प्राधिकरण द्वारा बनाया गया निर्यातकर्ता का रजिस्टर अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्यातकर्ता के रूप में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख के रूप में है;
- (xi) “रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता” से अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निर्यातकर्ता अभिप्रेत है;
- (xii) “विनियम” से अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;
- (xiii) “अनुसूची” से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (xiv) “अनुसूचित उत्पाद” से अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित कोई कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद अभिप्रेत है;
- (xv) “सचिव” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;
- (xvi) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
- (xvii) “वर्ष” से अप्रैल के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाला और पश्चातवर्ती आगामी मार्च की 31 तारीख को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

## अध्याय 2

### प्राधिकरण की अधिवेशनों की प्रक्रिया

3. प्राधिकरण के अधिवेशन- (1) किसी वर्ष में प्राधिकरण की कम-से-कम तीन साधारण अधिवेशन ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और किन्हीं दो साधारण अधिवेशनों के मध्य अंतराल किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगा। प्राधिकरण का पहला अधिवेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में होगा।

(2) अध्यक्ष, अत्यंत आवश्यकता की दशा में किसी भी समय प्राधिकरण का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और ऐसा तब भी कर सकेगा यदि कम-से-कम आठ सदस्यों द्वारा लिखित में उसे ऐसे अधिवेशनों के लिए ऐसी अध्यक्षता प्रस्तुत की जाती है जिसमें अध्यक्षित अधिवेशन का प्रयोजन और उसमें विचार करने के लिए कारबार उपवर्णित किया गया हो।

4. आमंत्रित करने की अध्यक्ष की शक्ति : अध्यक्ष, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और ऐसा आमंत्रित व्यक्ति अधिवेशन की कार्रवाहियों में भाग ले सकेगा किन्तु ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा।

5. केन्द्रीय सरकार की अधिवेशन बुलाने की शक्ति :- इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी भी समय प्राधिकरण का अधिवेशन बुला सकेगी।

6. साधारण अधिवेशनों की सूचना :- प्राधिकरण के किसी साधारण अधिवेशन से पहले 14 पूर्ण दिन की सूचना आशयित अधिवेशन का समय, तारीख और स्थान की सूचना देते हुए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ी या डाक द्वारा भेजी जाएगी।

7. गणपूर्ति—(1) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में कोई कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए कम-से-कम आठ सदस्य ऐसे अधिवेशन में उपस्थित न हों।

(2) यदि किसी समय किसी अधिवेशन में सदस्यों की संख्या उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम हो तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान की सदस्यों को सूचना देने के पश्चात् अधिवेशन स्थगित करेगा और ऐसे स्थगित अधिवेशन करने वाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना मूल अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने के लिए आशयित कारबार को निपटाए।

8. अधिवेशन का अध्यक्ष :- अध्यक्ष प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए उनमें से एक का चयन करेंगे।

9. कार्यसूची—(1) अध्यक्ष साधारण अधिवेशन की दशा में प्राधिकरण के अधिवेशन से कम-से-कम दस दिवस पहले ऐसे अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने के लिए कारबार की सूची तैयार कराएगा और केन्द्रीय सरकार तथा प्राधिकरण के सदस्यों के बीच परिचालित कराएगा।

(2) कोई कारबार का संव्यवहार जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय प्राधिकरण के अधिवेशन में नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि कार्यसूची के जारी करने के पश्चात् उसका संशोधन या परिवर्धन करना विधिपूर्ण होगा।

10. मतदान :- (1) प्राधिकरण के अधिवेशन के समझ लाया गया प्रत्येक प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णयित किया जाएगा।

(2) समान मत होने की दशा में अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन का पीठासीन सदस्य द्वितीय या निर्णायक मत देगा।

11. परिचालन द्वारा कारबार : (1) ऐसा कोई कारबार जिसका संव्यवहार प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा सदस्यों को (ऐसे सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं हैं) निर्दिष्ट किया जाएगा और इन प्रकार परिचालित कागज पत्रों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित और सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प जिन्होंने लिखित में उनके दिशार व्यक्त किए हो, उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकर होगा मानो ऐसा प्रस्ताव या संकल्प किसी अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो :

परन्तु यह कि प्राधिकरण के कम से कम आठ सदस्यों ने प्रस्ताव या संकल्प का अनुमोदन किया हो :

परन्तु यह और कि जब तक कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कोई आठ सदस्य यह अपेक्षा कर सकेंगे कि प्रस्ताव या संकल्प प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां कोई कारबार उपविनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कम से कम पन्द्रह पूर्ण दिवस सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे और ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कारबार की सूचना निकाली जाती है।

(4) यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो ऐसे परिचालन का परिणाम कार्यसूची कागज-पत्रों के अभिलेख में उपवर्णित करके बोर्ड के आगामी अधिवेशन में सभी सदस्यों को और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।

12. प्राधिकरण के समक्ष रखे जाने वाले कागज पत्र :- कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा इस प्रकार विनिश्चित प्रश्नों से संबंधित सभी कागज पत्र अभिलेख के लिए प्राधिकरण के आगामी अधिवेशन में रखे जाएंगे।

13. कारबार का अभिलेख— (1) प्राधिकरण का सचिव प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहेगा और उसमें संव्यवहार किए गए कारबार की सभी मदों की कार्यवाहियों का उसके द्वारा अभिलेख रखा जाएगा। ऐसे अभिलेख की प्रतियां उक्त अधिवेशन की तारीख से तीस दिवस के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी :

परन्तु यदि किसी कारण से सचिव, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ हो तो ऐसा कोई पदधारी या अन्य कृत्यकारी, जिसे अध्यक्ष इस अस्थायी प्रयोजन के लिए पदामिहित करें, यह विधिपूर्ण होगा कि वह कार्यवाहियों का अभिलेख लिखे।

(2) जब विनियम (9) के अधीन कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार किया जाता है तब इस प्रकार संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(3) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में संव्यवहारित कारबार का अभिलेख, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन के पीठासीन सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(4) प्राधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय और निदेश प्राधिकरण के संकल्प के रूप में अभिलिखित, निर्दिष्ट और संसूचित किया जाएगा।

### अध्याय - 3

#### प्राधिकरण की समितियां

14. समितियों की नियुक्ति — प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान आयोजित की जानेवाली अपनी पहली अधिवेशन में संकल्प द्वारा निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा, अर्थात् :-

(अ) कार्यपालक समिति

(आ) निम्नलिखित उत्पाद समूह के लिए एक समिति होगी जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद समिति कहा गया है जो उसके गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद भार धारण करेगी :

क) ताजी और प्रसंस्कृत फल और सब्जियां तथा अन्य प्रसंस्कृत और प्रकीर्ण उत्पाद

ख) पशु उत्पाद

ग) पुष्प कृषि, बीज और अनाज

कार्यपालक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(i) अध्यक्ष, जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा :

(ii) निदेशक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास (एपीडा)

(iii) वाणिज्य मंत्रालय में निर्यात संवर्द्धन (कृषि) प्रभाग का भारसाधक निदेशक/उपसचिव,

(iv) वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक/उपसचिव (वित्त)

(v) सचिव ; और

(vi) प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा, उनमें से उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की जाए, निर्वाचित किए जाने वाले पांच अन्य सदस्य।

प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए उत्पाद समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(i) अध्यक्ष, जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा।

(ii) निदेशक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।

(iii) सचिव या उत्पाद समूह से संबंधित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी जिसे सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए।

(iv) प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उनमें से उस रीति में जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत की जाए, निर्वाचित किए जाने वाले पांच सदस्य ।

15. समितियों के कृत्य - (1) कार्यपालक समिति, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, ऐसे कृत्यों के अतिरिक्त जो उसे इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित किए गए हैं, उत्पाद समिति को इसके अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित नहीं किए गए विषयों के संबंध में प्राधिकरण के अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगी ।

(2) प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए समिति, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किए जाएं, समिति को समनुदेशित अनुसूचित उत्पादों से संबंधित सभी तकनीकी विषयों के संबंध में विमर्श, सलाह सिफारिश करेगी और विनिश्चय करेगी और ऐसे उपायों पर भी सलाह देगी जो समिति को समनुदेशित अनुसूचित उत्पादों के संबंध में कार्यकलापों के विकास के लिए किए जाएं ।

कार्यपालक समिति और उत्पाद समितियों की शक्तियां - प्राधिकरण की प्रत्येक समिति के पास प्राधिकरण की सभी शक्तियां होंगी और किसी भी समिति द्वारा किया गया प्रत्येक विनिश्चय प्राधिकरण का विनिश्चय समझा जाएगा, परन्तु प्रत्येक समिति का प्रत्येक विनिश्चय जो नीतिगत प्रकृति का है या जिसमें प्राधिकरण या सरकार से निकाली जाने वाली निधियों के रूप में 5 लाख रुपए या उससे ऊपर की वित्तीय विवक्षाएं अंतर्बलित हैं उसे प्राधिकरण के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और यदि विनिश्चय को आठ या अधिक सदस्य, उनको उनको विनिश्चय की सूचना जारी किए जाने की तारीख से 14 दिन के भीतर विनिश्चय पर आक्षेप करते हैं तो उसका कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया जाएगा ।

16 प्राधिकरण की पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने की शक्ति - प्राधिकरण को किसी समिति के किसी विनिश्चय का प्राधिकरण की किसी विशेष या साधारण अधिवेशन में पुनर्विलोकन करने, परिवर्धित करने और उसका संशोधन करने का अधिकार और शक्ति प्राप्त है, यह इस शर्त के अधीन होगा कि पहले से की गई या निष्पादित की गई संदिग्धताएं या पुनर्विलोकनाधीन विनिश्चयों के भाग जिन्हें पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है वे प्राधिकरण द्वारा पुनर्विलोकन या संशोधन अथवा पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होंगे ।

17. कार्यपालक समिति और उत्पाद समितियों का गठन- (1) प्राधिकरण साधारण अधिवेशन में प्रत्येक समिति की सदस्यता का विनिश्चय करेगा ।

(2) प्राधिकरण द्वारा समिति में नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस पद को प्राधिकरण का सदस्य रहने तक या समिति की कालावधि तक, जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा ।

18 तदर्थ समितियां - (1) प्राधिकरण, किसी साधारण या विशेष अधिवेशन में प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों सहित जिसे वह उचित समझे, कार्यपालक समिति या उत्पाद समिति से भिन्न एक या अधिक समितियों के गठन का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण के सदस्यों में से ऐसी अवधि के लिए जिसे वह अवधारित करे उसके सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगा ।

(3) कार्यपालक समिति या उत्पाद समिति से भिन्न प्रत्येक ऐसी समिति केवल ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे सौंपी गई है, और ऐसी शक्तियां जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई हैं प्रयोग करेगी ।

19. अध्यक्ष की मंजूरी के अधीन रहते हुए समितियों के विनिश्चय का कार्यान्वयन- किसी समिति का कोई विनिश्चय सभापति की विनिर्दिष्ट मंजूरी के बिना कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा ।

#### अध्याय- 4

##### समितियों की अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया

20. सभापति का अधिवेशन बुलाने की शक्ति - अध्यक्ष किसी भी समय किसी समिति का अधिवेशन बुला सकेगा और ऐसा ही तब कर सकेगा जब उस समिति की आवश्यक सदस्य संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित में उससे अधिवेशन बुलाए जाने की मांग प्रस्तुत की हो, उसमें अधिवेशन बुलाए जाने का प्रयोजन और किए जाने वाले कारबार के संव्यवहार के बारे में उल्लेख होगा ।

21. अधिवेशन की सूचना - (1) अध्यक्ष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा ऐसे अपेक्षा या आमंत्रित किए गए अधिकारी या व्यक्ति को अधिवेशन में उपस्थित होने का अधिकार होगा किन्तु वह ऐसी अधिवेशन में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(2) आशयित अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कम से कम 15 दिन पहले समिति के प्रत्येक सदस्य के पते पर दी जाएगी या डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

22. लघु सूचना पर विशेष अधिवेशन—अत्यावश्यकता की दशा में किसी समिति की विशेष अधिवेशन ऐसी लघुतर सूचना पर जो आवश्यक और साध्य हो किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकेगी जो उसके सदस्यों को विमर्श किए जाने के लिए विषय-वस्तु और उसके कारणों को बताते हुए जिसके लिए वह ऐसा अत्यावश्यक अधिवेशन बुलाना आवश्यक समझते हैं अग्रिम सूचना देंगे ;

परन्तु यह और कि किसी समिति के ऐसे विशेष अधिवेशन में कोई साधारण कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

23. केन्द्रीय सरकार को सूचना दिया जाना - किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

24. कार्यसूची - (1) सम्बद्ध समिति का अध्यक्ष समिति के अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पूर्व ऐसे अधिवेशन में संबद्धरित किए जाने वाले कारबार की एक सूची तैयार कराएगा और समिति के सभी सदस्यों को परिचालित करेगा

(2) किसी समिति की किसी अधिवेशन में उसके अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी कारबार का, जो कार्यसूची में पहले से ही या तत्पश्चात् सम्मिलित नहीं किया गया है, संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(3) समिति का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार को, प्रत्येक अधिवेशन के 15 दिन के भीतर, परिचालित किया जाएगा ।

25. गणपूर्ति - (1) किसी समिति के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति ऐसी समिति की कुल संख्या का एक बटा चार होगी ।

(2) यदि किसी समय समिति के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या उक्त विनियम (i) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम है तो, अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति अधिवेशन की तारीख से 7 दिन से अनधिक की अवधि के लिए अधिवेशन को आस्थगित कर देगा और समिति के सभी सदस्यों को आस्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा और अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे आस्थगित अधिवेशन में उपस्थित होनेवाले सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना मूल अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने के लिए आशयित कारबार का निपटारा करे ।

26. अधिवेशन का अध्यक्ष- (1) अध्यक्ष समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित सदस्यों में से नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(2) किसी समिति के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाले सभी प्रश्नों पर विनिश्चय उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों की समान संख्या होने की दशा में ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा ।

(3) जब तक कि ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति यह विनिश्चय नहीं करे कि मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा, सभी मत अधिवेशन में हाथ उठाकर लिए जाएंगे ।

(4) कोई कारबार जिसका किसी समिति द्वारा संव्यवहार किया जाना है यदि अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझे, कागज पत्रों को परिचालित करके ऐसी समिति के सदस्यों को ( उन सदस्यों से भिन्न जो भारत से अनुपस्थित हों) निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) ऐसी समिति के बहुमत सदस्यों द्वारा परिचालित और अनुमोदित कोई प्रस्ताव या संकल्प, जिस पर उन्होंने अपने विचार लिखित में अभिलिखित किए हैं उस प्रकार प्रभावी और आबद्धकर माने जाएंगे मानों ऐसे प्रस्ताव या संकल्प का विनिश्चय ऐसी समिति के बहुमत सदस्यों द्वारा अधिवेशन में किया गया हो ;

परन्तु यह कि ऐसी समिति के तीन सदस्य यह अपेक्षा करते हैं कि ऐसे प्रस्ताव या संकल्प को समिति की अधिवेशन में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए, तथा प्रस्ताव या संकल्प समिति के अधिवेशन में रखा जाएगा ।

(6) जहां कोई प्रस्ताव या संकल्प उपनियम (iv) के अधीन समिति के सदस्यों को कागज पत्रों के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है वहां उत्तरों की प्राप्ति के लिए 10 दिन की अनधिक की अवधि अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी अवधियों की गणना उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है, की जाएगी ।

(7) यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा ।

(8) कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किए गए सभी दिनिश्चय समिति को आगामी अधिवेशन के अभिलेख के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(9) किसी प्रस्ताव या संकल्प की प्रतियां और कागज पत्रों के परिचालन के परिणाम उनके परिचालन संसूचित किए जाने के समय यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या समिति के सदस्यों को भेजे जाएंगे।

27. कारबार का अभिलेख -- प्राधिकरण का सचिव और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा यथाअपेक्षित प्राधिकरण का कोई अधिकारी प्रत्येक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और समिति के सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और समिति के सभी अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखेंगे जो सभापति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। प्रत्येक समिति के लिए पृथक कार्यवाही बही रखी जाएगी।

#### अध्याय - 5

प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा शर्तें आदि

28.(1) प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक द्वारा की जाएगी :

(क) सीधी भर्ती

(ख) प्रेन्तति

(ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं सरकारी/स्वशासी संगठनों से प्रतिनियुक्ति

(घ) संविदा नियुक्ति

(2) सीधी भर्ती की पद्धति को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के विभिन्न काडर निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकेंगे :-

समूह क - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 13500 रूपए से अन्यून हो।

समूह ख - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 9000 रूपए से अन्यून किन्तु 13500 रूपए से कम हो।

समूह ग - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4000 रूपए से अन्यून हो किन्तु 9000 रूपए से कम हो।

समूह घ - ऐसा पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4000 रूपए या उससे कम हो।

(3) यदि पुनर्स्थापन महानिदेशालय उचित समझे तो, समूह ख, समूह ग और समूह घ पदों पर भर्ती रिक्तियों को रोजगार कार्यालय में अधिसूचित कर के की जाएगी, परन्तु यह कि समूह ख, समूह ग और समूह घ पदों की प्रश्नगत रिक्तियों की दशा में उनकी बाबत अध्यक्ष पूर्व अनुभव अपेक्षित समझता है तो भर्ती पदों को विज्ञापित करके भी की जाएगी।

(4) समूह क पदों की दशा में भर्ती उन अभ्यर्थियों में से जो, अखिल भारतीय स्तर पर इस निमित्त विज्ञापन के संदर्भ में आमंत्रित आवेदन पत्रों के उत्तर में अधिकथित न्यूनतम पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं, चयन द्वारा की जाएगी।

(5) अभ्यर्थियों की आरंभिक रूप से छटनी और अंतिम चयन के प्रयोजन के लिए प्रारंभिक प्रतियोगितात्मक परीक्षण और साक्षात्कार परीक्षा दोनों जिसकी यथास्थिति अध्यक्ष, कार्यपालक समिति या प्राधिकरण द्वारा उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर पदों की बाबत विनिश्चित की जाएं, आयोजित की जाएगी।

(6) वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(7) प्राधिकरण के अधीन इस पद पर नियुक्ति करने से पूर्व प्राधिकरण के लिए निम्नलिखित में से कोई या सभी करना विधिपूर्ण होगा :-

(क) अभ्यर्थी के सद्वस्त्रि होने के सबूत पेश करने की वाछ।

(ख) प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा और पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी विशिष्टियां, उसका पता और ठिकाना, उसके पूर्ववृत्त इत्यादि प्रस्तुत करने की वाछ।

(ग) स्वस्थ धित और शारीरिक स्वास्थ्य के सबूत की वाछ और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त यह निवेश भी दिया जा सकेगा कि प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट पेनल विशदज्ञ या चिकित्सक से स्वास्थ्य का ऐसा प्रमाण पत्र भी लिया जाए।

- (घ) प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति की प्राधिकरण के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व वृत्ती का स्थापन करना ।
- (ग) “ प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भर्ती नियमों में जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रथक रूप से अधिसूचित किए जाने हैं विनिर्दिष्ट परीक्षा के उपबंधों के अनुसार परीक्षा पर रहेगा । ”
- (ग) अध्यक्ष ऐसे प्रस्तर, प्रक्रियाएं, प्रपत्र आदि को जो ऊपर उपविनियम (5), (6), और (7) के लिए आवश्यक और अनुलग्नक हों, बना और विहित कर सकेगा ।
- (क) अध्यक्ष, ऐसे सभी पदों के लिए जिनका अधिकतम वेतनमान 13,500 रुपए से कम नहीं है, नियुक्ति प्राधिकारी होगा, परन्तु यह कि उसके द्वारा की गई सभी नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर पदों पर होगी और वह इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण की कार्यपालक समिति और केन्द्रीय सरकार को करेगा ।
- (ख) ऐसे पदों पर जिनका अधिकतम वेतनमान 13,500 रुपए से कम नहीं है सभी नियुक्तियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे बाबत समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार या तो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के उपयुक्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी ।
- (ग) कार्यपालक समिति उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती में उसकी सहायता करने वाली ऐसी युक्तियां और प्रक्रियाएं बना सकती हैं जिन्हें वह उचित समझे । यद्यपि जहां ऐसी कोई प्रक्रियाएं विहित नहीं की गई हैं वहां अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा अंतिम चयन की स्थिति तक इस बाबत सभी कदम उठाएगा और समिति द्वारा चयनित व्यक्ति की नियुक्ति करेगा ।
- (ख) अध्यक्ष या समिति सहयोग कर सकेगी व अन्य रूप से भर्ती और चयन कार्य में सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगी तथा जहां ऐसा सहयोगन साम्प्रदायिक में सहायता के प्रयोजन के लिए किया गया है वहां इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस बाबत निश्चित मानदेय संवत्त किया जा सकेगा ।
- (घ) प्राधिकरण उचित समझे जाने पर संविदा सेवाएं ले सकेगा । 6 मास से अधिक अवधि की और/या 1800 रुपए अथवा अधिक के मूल मासिक पारिश्रमिक वाले कोई संविदा नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना नहीं की जाएगी ।
- (घ) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की, पदेन्नति द्वारा किसी नियुक्ति पर विचार करने या आयु वर्जन स्थगित करते हुए प्राधिकरण में नियुक्ति करने पर कोई वर्जन नहीं होगा, परन्तु यह कि:-
- (i) कर्मचारी के पास अन्य अपेक्षित अर्हताएं हैं, और
  - (ii) कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त समझा जाता है ।
- (ख) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर भर्ती, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रथकतः अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे पदों के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

## अध्याय VI

### प्राधिकरण का वित्त पोषण, बजट और सेवा

29. **बजट प्रावकलन :-** (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ऐसी तारीखों को या पहले मंजोगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
- (2) जब तक केन्द्रीय सरकार बजट को मंजूर नहीं करती और सक्षम प्राधिकारियों से उस व्यय की मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा ।
- (3) बजट में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित होगा :-
- (क) प्रावकलित प्रारम्भिक अतिशय;



- (क) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राक्कलित प्राप्तिवां,  
 (ग) ऐसे विभिन्न शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन वर्गीकृत प्राक्कलित व्यय जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदेश करे ;  
 (4) अनुपूरक प्राक्कलित व्यय यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रश्न और ऐसी तारीखों को, जो इसके द्वारा इस बात निर्देशित की जाएं मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ।  
 (5) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, व्यय के शीर्षों और उपशीर्षों के बीच पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।

## अध्याय VII शक्तियों का प्रत्यायोजन

30. व्यय मंजूर करने की शक्तियाँ- (1) प्राधिकरण का किसी उपनिदेशक/प्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी के पास, जिसके अध्यक्ष द्वारा कार्यालय का प्रधान विनिर्दिष्ट किया जाए, पांच सौ रुपये तक का आवर्ती व्यय और किसी एक मद पर कार्यालय आकस्मिकता, आपूर्तियों और सेवाओं से संबंधित एक हजार रुपये तक का अनावर्ती व्यय, उस मद से संबंधित बजट उपबंधों के उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए, मंजूर करने की शक्ति होगी ।

अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम के अनुसरण में प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अपनी वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

- (2) किसी सहायक निदेशक अथवा समतुल्य रैंक के अधिकारी के पास किसी एक समय पर किसी एक मद के लिए कार्यालय आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं से संबंधित पांच सौ रुपये तक का अनावर्ती व्यय, उस मद से संबंधित बजट उपबंध उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए, मंजूर करने की शक्ति होगी ।  
 31. हानियाँ और अपलिखित करने, संविदाओं तथा पट्टा दिलेख करने और निष्पादित करने की शक्ति ।

- (1) अध्यक्ष के पास पांच सौ रुपये तक की रकम को अवसूलीय हानि के रूप में अपलिखित करने की शक्ति होगी सचिव को अवसूलीय हानि के रूप में दो सौ पचास रुपये तक की रकम को अपलिखित करने की शक्ति होगी ।  
 (2) प्राधिकरण इसके द्वारा उपगत दस हजार रुपये तक की हानि को यदि किसी एक मामले में यह हानि चोरी, कपट और उपेक्षा के कारण हुई है और किसी एक मामले में बीस हजार रुपये तक की हानि को जहां ऐसी हानि लोक-धन, राजस्व अथवा प्राप्तिवां, भंडारों या प्राधिकरण द्वारा या इसकी ओर से धारित किसी अन्य सम्पत्ति से संबंधित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी साधारण शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, अपलिखित कर सकेगा । किसी वर्ष में अपलिखित हानियों की कुल रकम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी । इस रकम से अधिक की हानियाँ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपलिखित की जाएंगी ।  
 (3) अध्यक्ष के पास ऐसी संविदाएं करने की शक्ति होगी जिनकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और जिनमें पचास हजार रुपये से अधिक का व्यय नहीं होगा । प्राधिकरण अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए कोई संविदा कर सकेगा :

परन्तु यह कि तकनीकी सहयोग के लिए प्रत्येक करार या सांविदा करने के लिए अथवा किसी फर्म या विदेशी सरकार से परामर्श करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी ।

- (4) अध्यक्ष के पास पट्टा दिलेख और मुखतास्नामा निष्पादित करने की शक्ति होगी ।  
 (5) सचिव के पास ऐसे पट्टा दिलेख और मुखतास्नामा निष्पादित करने की शक्ति होगी जिनके निष्पन्न और शर्तों का अध्यक्ष ने अनुमोदन कर दिया है ।  
 (6) अध्यक्ष अपनी प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की यात्राओं और दैनिक मत्तों के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा :  
 परन्तु यह कि अध्यक्ष, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्राधिकरण के किसी ऐसे कर्मचारी के, जिसके वेतनमान में न्यूनतम वेतन 3050 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, यात्रा दैनिक मत्तों के संबंध में नियंत्रक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।  
 (7) रकमों का निक्षेप या विनिधान या निकालने वाले अथवा प्राधिकरण की निधियों का किसी अन्य रीति में व्ययन करने वाले सभी चैक और सभी आदेश :-

- (क) यदि चैक और आदेश 25,000 रुपए से अनधिक रकम के हैं तो सचिव द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
- (ख) यदि चैक और आदेश 25,000 रुपए से अधिक रकम के हैं तो सचिव द्वारा और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और सचिव की अनुपस्थिति में ऐसे चैक, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारियों हस्ताक्षरित होंगे।

32. प्राधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित शक्तियाँ :-

- (1) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों जिनमें की अधिवर्षिता की आयु और अन्य सुविधाओं जैसे अग्रिम वेतन, वाहन की खरीद, घरों के निर्माण तथा उन उपबन्धों के लिए अग्रिम, के संबंध में यदि इन विनियमों में या अन्य रूप से कोई उपबंध नहीं किए गए हैं तो वे ऐसे नियम एवं विनियमों से विनियमित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे स्थानों पर तैनात समान ग्रेड और हैसियत वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हैं सिवाय ऐसे उपबंधों के जो सेवा निवृत्ति के बाद होने वाले फायदों से, जैसे पेंशन, साधारण भविष्य निधि, चिकित्सीय प्रतिपूर्ति, संबंधित हैं।
- (2) सिवाय तब कि जब विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित हो, प्राधिकरण का प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवा निवृत्ति की आयु वर्तमान में 58 वर्ष है, उस मास के अंतिम दिन में अपराह्न को, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता/करती है सेवा से निवृत्त होगा। यद्यपि ऐसे कर्मचारी, जिनके जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त होंगे।
- (3) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को, अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् विस्तारण देने पर पूर्ण पाबंदी होगी सिवाय ऐसे मामलों के जहां सेवा में विस्तारण को न्यायोचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, यहां मामला दर मामला के आधार पर केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से विस्तारण किया जाएगा।

33. विदेश में प्रतिनियुक्ति से संबंधित शक्तियाँ :- प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी या प्राधिकरण के सदस्य को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पूर्ण अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं भेजेगा।

एस. एम. आचार्य, संयुक्त सचिव

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/153/99]

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना फा. सं. से क./एआईआर/02/93 दिनांक 18 जनवरी, 1994 द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1999

F. No.-11/5/86-EP (Agrl.-IV).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), and in supersession of The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulation 1986 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, as required under sub-section (1) of the said section hereby makes the following regulations, namely:-

Chapter I

Preliminary

1. Short title and commencement: - (1) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1999.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (i) "Act" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);
- (ii) "Authority" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority established under section 4 of the Act;
- (iii) "Chairman" means the Chairman of the Authority;
- (iv) "Committee" means any of the Committees appointed by the Authority under section 9 of the Act ;
- (v) "Competent Authority" means the Chairman of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority;
- (vi) "Director" means the Director of the Authority;
- (vii) "Employee" means any person in the full time employment of the Authority irrespective of the scale of pay or status;
- (viii) "Government including Central Government " means Government of India in the Ministry of Commerce or, in any other context, in the appropriate Ministry;
- (ix) "Member" means member of the Authority and includes the Chairman;
- (x) "Register" means Register of Exporters maintained by the Authority as a record of all such persons registered by it as exporters under section 12 of the Act;
- (xi) "Registered Exporters" means an exporter registered under section 12 of the Act;
- (xii) "Regulations" means regulations made under the Act;
- (xiii) "Schedule" means the Schedule of the Act;
- (xiv) "Scheduled Products" means any of the agricultural or processed food products included in the Schedule to the Act;
- (xv) "Secretary" means the Secretary to the Authority appointed under section 7 of the Act;
- (xvi) "section" means a section of the Act;
- (xvii) "Year" means the financial year commencing on the first day of April and ending with the 31st day of March next following.

## CHAPTER-II

### Procedure for meetings of the Authority

3. Meeting of the Authority -(1) There shall be not less than three ordinary meetings of the Authority in a year on such dates and at such places as the Chairman may think fit and the interval between any two ordinary meetings shall not in any case, be longer than six months. The first meeting of the Authority shall be held in the first quarter of every financial year.

(2) The Chairman may, in case of urgency, at any time, call a special meeting of the Authority and may also do so if a requisition for such meetings is presented to him in writing by atleast eight members, setting out therein the purpose of the Meeting requisitioned and the business to be considered there at.

4. Power of Chairman to invite: The Chairman may invite any officer of the Authority or any other person to attend any meeting of the Authority, and any such invitee may participate in the proceedings of the meeting, but such officer or person shall not be entitled to vote.

5. Power of Central Government to call meetings: - Notwithstanding anything contained in these regulations, the Central Government may, at any time, call a

6. Notice of ordinary meetings:- At least 14 clear days' notice before any ordinary meeting of the Authority, intimating the time, date and place of the intended meeting signed by the Secretary shall be sent to the Central Government and left at or posted to the address of every member.

7. Quorum - (1) No business shall be transacted at a meeting of the Authority unless there are present at such meeting atleast eight members, including the Chairman.

(2) If at any time the number of members at a meeting is less than the number of members specified in sub-regulation (1), the person presiding shall adjourn the meeting after informing the members of the date, time and place of the adjourned meeting and it shall thereupon be lawful for the person presiding at such adjourned meeting to dispose of the business intended to be transacted at the original meeting, irrespective of the number of members present.

8. Chairman of meetings:- The Chairman shall preside over every meeting of the Authority and, in his absence, the members present at the meeting shall elect one from among themselves to preside over such meeting.

9. Agenda - (1) The Chairman shall cause to be prepared and circulate to the Central Government and among the members of the Authority atleast ten days before a meeting of the Authority, in case of ordinary meeting, the list of business to be transacted at such meetings.

(2) No business not included in the Agenda shall be transacted at a meeting of the Authority except with the permission of the Chairman:

Provided that it shall be lawful to amend or add to the agenda subsequent to its issue.

10. Voting:- (1) Every question brought before a meeting of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.

(2) In the case of an equality of votes, the Chairman or the member presiding over such meeting shall have a second or casting vote.

11. Business by circulation:- (1) Any business which is to be transacted by the Authority may, if the Chairman so directs, be referred to members (other than members who are not in India) by circulation of papers and copies of papers so circulated shall also be sent to the Central Government.

(2) Any proposal or resolution circulated under sub-regulation (1) and approved by the majority of the members who have recorded their views in writing shall be a effectual and binding as if such proposal or resolution were decided by the majority of the members at a meeting:

Provided that atleast eight members of the Authority have approved the proposal or resolution.

Provided further when a proposal or resolution, is referred to members by circulation any eight members may require that the proposal or resolution be referred to the members at a meeting of the Authority.

(3) Where any business is referred to members under sub-regulation (i), a period of not less than fifteen clear days shall be allowed for the receipt of replies from members and such period shall be reckoned from the date on which the notice of business is issued.

(4) If a proposal or resolution is circulated under this regulation the result of such circulation shall be communicated to all members at the next meeting of the Board by way of a mention on record in the Agenda papers and to the Central Government.

12. Papers to be placed before the Authority - All papers relating to questions so decided by circulation of papers shall be placed at the next meeting of the Authority for record.

13. Record of business: - (1) The Secretary of the Authority shall attend all meetings of the Authority and record of proceedings be maintained by him of all items of the business transacted thereat. Copies of such record shall be forwarded to the Central Government within thirty days from the date of the said meeting.

Provided that if for any reasons the Secretary is unable to attend any meeting of the Authority, it shall be lawful for and incumbent upon any other functionary, the Chairman may for this temporary purpose designate, to write the record of the proceedings.

(2) when a business is transacted by circulation of papers under regulations (9), a record of business so transacted shall be signed by the Chairman.

(3) The record of business transacted at every meeting of the Authority shall be signed by the Chairman, or the member presiding over such meeting, as the case may be.

(4) Every decision and direction of the Authority shall be recorded, referred to and communicated as resolution of the Authority.

**CHAPTER-III****COMMITTEES OF THE AUTHORITY**

14. Appointment of Committees- The Authority shall at its first meeting to be held during the first quarter of every financial year by resolution appoint the following Committees, namely:-

(A) An Executive Committee

(B) A Committee hereinafter referred to as Product Committee for each of the following product group which shall hold office for a period of one year from the date of their formation :-

- a) Fresh and Processed Fruits and Vegetables and other processed and miscellaneous products.
- b) Animal Products
- c) Floriculture, Seeds and Cereals

The Executive Committee shall consist of :-

- (i) The Chairman, who shall be the ex-officio Chairman thereof.
- (ii) Director of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA).
- (iii) Director/Deputy Secretary incharge of Export Promotion (Agriculture) Division in the Ministry of Commerce.
- (iv) Director/Deputy Secretary(Finance) in the Ministry of Commerce.
- (v) The Secretary; and
- (vi) Five other members to be elected by members of the Authority from amongst themselves, in such manner as may be laid down by the Authority.

The Product Committee for each of the product group shall consist of:-

- (i) The Chairman who shall be the ex-officio Chairman thereof.
- (ii) Director of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority.
- (iii) The Secretary or an officer of the Agricultural and Processed Food Export Development Authority concerned with the product group nominated by the Chairman.

- (iv) Five members to be elected by the members of the Authority from amongst themselves in such manner as may be laid down by the Authority.

**15. Functions of the Committees -** (1) Subject to such restrictions as may be imposed by the Authority, the Executive Committee shall in addition to such functions as have been specifically assigned to it under these regulations discharge any other functions of the Authority in regard to matters not specifically assigned hereunder to the Product Committee.

(2) Subject to such restrictions as may be imposed by the Authority, the Committee for each product group shall discuss, advise recommend and decide on all technical matters related to Scheduled Products assigned to the Committee and also advise on measures that may be undertaken for the development of activities connected with the Scheduled Products assigned to the Committee.

**Powers of the Executive Committee and Product Committee(s) -** Each of the Committees of the Authority shall have all the powers of the Authority itself and every decision taken by any of the Committee shall be treated as a decision of the Authority, provided that every decision of each of the Committee of a policy nature or having financial implications of Rs.5 lakhs or above by way of an outgo of the funds of the Authority or of the Government shall be communicated to all the members of the Authority, and implementation thereof shall be withheld if eight or more members object to the decision within 14 days of the date of issue of the intimation of the decision to them.

**16. Power of Authority to review and revise.** - The Authority shall have the right and power to review, alter, and to or amend any decision of any Committee at any Special or Ordinary Meeting of the Authority, subject to the condition that contracts already entered or executed or portions of the decisions under review already implemented shall not be subject to alteration or amendment or review by the Authority.

**17. Constitution of Executive Committee and Product Committee(s) -** (1) The Authority shall at an ordinary meeting decide the membership of each Committee.

(2) A person nominated to a Committee by the Authority shall hold that office till he remains a Member of the Authority or the tenure of the Committee whichever is earlier.

**18. Adhoc Committees -** (1) The Authority may at any ordinary or special meeting decide to constitute one or more Committees other than the Executive

Committee or Product Committee for each product Group for such purposes and with such powers, functions and duties as it may consider appropriate:

(2) And may appoint there to members from amongst the members of the Authority for such period as it may determine.

(3) Every such Committee other than the Executive Committee or Product Committee shall discharge only such functions and duties as are entrusted to it and shall exercise only such powers as are conferred upon it by the Authority.

19. Implementation of decisions of the Committees subject to sanction of Chairman - No decision of any Committee shall be implemented without the specific sanction of the Chairman.

#### CHAPTER-IV

##### Procedure for meetings of Committees

20. Power of Chairman to call meeting - (1) The Chairman may, at any time, call a meeting of a Committee and may also do so if a requisition for a meeting of the Committee is presented to him in writing by at least one half of the total number of members of that Committee, stating therein the purpose of the requisitioned meeting and the business to be transacted.

21. Notice of meeting - (1) The Chairman may require any officer of the Authority or invite any other person to attend any meeting of the Committee by the officer or person so required or invited but he shall not be entitled to vote at such meetings.

(2) At least 15 clear days' notice of the time and place of the intended meeting signed by the Secretary shall be left at, or posted to, at the address of every member of the Committee.

22. Special meeting at short notice - In cases of urgency, special meetings of a committee at a shorter notice as may be necessary and practicable may be summoned at any time by the Chairman, who shall inform in advance the members thereof, of the subject matter for discussion and the reason for which he considers the summoning of such meeting urgently:

Provided further that no ordinary business shall be transacted at such special meetings of a Committee.

23. Central Government to be given notice - Notice of every meeting of a Committee shall be sent to the Central Government.



**24. Agenda -** (1) The Chairman of the Committee concerned shall cause to be prepared and circulated to all the members of the Committee, atleast 15 days before a meeting of the Committee, a list of business to be transacted at such meeting.

(2) No business, not initially or subsequently included in the agenda, shall be transacted at a meeting of a Committee, without the permission of its Chairman.

(3) The minutes of the Committee shall be prepared and circulated to the members as well as the Central Government within 15 days from the date of each meeting.

**25. Quorum -** (1) The quorum for a meeting of any Committee shall be one fourth of the total number of members of such Committee.

(2) If at any time the number of members present at a meeting of a Committee is less than the number specified in sub-regulation(i), the person presiding shall adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the meeting and inform all the members of the Committee about the date, time and place of the adjourned meeting and it shall thereupon be lawful for the person presiding to dispose of, at such adjourned meeting, the business intended to be transacted at the original meeting irrespective of the number of members attending.

**26. Presiding officer of meeting -** (1) The Chairman shall preside over the meetings of a Committee, and in the absence of the Chairman, a person elected by the members of the Committee from amongst the members present shall preside over such meetings.

(2) All questions which may come up for decision before a meeting of any Committee shall be decided by a majority of the members thereof present and voting at such meeting and in the event of an equality of votes, the person presiding over such meeting shall have a second or casting vote.

(3) All votes at a meeting shall be taken by show of hands unless the person presiding over such meeting decides that the votes shall be taken by secret ballot.

(4) Any business which has to be transacted by a Committee may, if the Chairman so considers necessary, be referred to the members of such Committee (other than the members who are absent from India) by circulation of papers.

(5) Any proposal or resolution circulated and approved by a majority of the members of such Committee who have recorded their views in writing shall be as

effectual and binding as if such proposal or resolution were decided by the majority of the members of such Committee at a meeting:

Provided that if three members of such a Committee require that the proposal of resolution be referred to members at a meeting of the Committee, the proposal or resolution shall be placed at a meeting of the Committee.

(6) Where a proposal or resolution is referred to the members of a Committee by circulation of papers under sub regulation (iv), a period of not less than ten days shall be allowed for the receipt of replies and such periods shall be reckoned from the date on which such proposal or resolution is circulated.

(7) If a proposal or resolution is circulated under this regulation, the result of circulation shall be communicated to all members of the Committee.

(8) All decisions arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting of the Committee, for record.

(9) Copies of any proposal or resolution and the result of circulation of papers shall also be sent to the Central Government at the time of its circulation or communication, as the case may be, to the members of the Committee.

27. Record of business - The Secretary of the Authority and in his absence any other officer of the Authority so required by the Chairman shall function as the Secretary of each Committee and shall attend all meetings of the Committee and maintain a record of the proceedings of all meetings of the Committee which shall be signed by the Chairman. Separate Proceedings Books shall be maintained for each Committee.

## CHAPTER-V

### Methods of Recruitment, conditions of service, etc. of employees of the Authority.

28 (1) Appointment to the service of the Authority may be made by any one of the following methods:

- (a) Direct Recruitment
- (b) Promotion
- (c) Deputation from the Central Government or a State Government or from any other Government/autonomous organisations.
- (d) Contract Appointment

(2) For the purpose of determining method of direct recruitment, the various cadres in the Authority may be categorised as follows:-

Group A- A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 13500/-

Group B- A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 9000/- but less than Rs.13,500/-.

Group C- A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4000/- but less than Rs. 9000/-.

Group D- A post carrying a pay or a scale of the maximum of which is Rs. 4000 or less.

(3) Recruitment to Group B,C and D posts shall be made by notifying vacancies to the Employment Exchange and if deemed fit, Directorate General of Resettlement, provided that in the event of vacancies in question of Group B, C and D posts in respect of which the Chairman considers previous experience desirable, recruitment may be made by advertising the post also.

(4) In the case of Group A posts, recruitment shall be made on the basis of selection from amongst the candidates fulfilling minimum eligibility criteria as may be laid down and answering to the advertisement in this behalf on All India basis, inviting applications.

(5) Preliminary competitive tests and interviews may be conducted both for the purpose of initial short listing of candidates and for final selection as may be decided by the Chairman, Executive Committee or Authority as the case may be in respect of posts within their respective jurisdictions.

(6) No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(7) Before making an appointment to a post under the Authority, it shall be lawful for the Authority to do any or all of the following:-

- (a) Seek production of proof of good character of the candidate.
- (b) Seek furnishing of declaration as to marital status and all other particulars necessary to establish the identity of the proposed appointee, his address and whereabouts, his antecedents etc.
- (c) Seek proof of sound mental and physical health and may, for that purpose, in addition direct that such certificate of health be also obtained from a Panel Specialist or Physician nominated by the Authority.
- (d) Verify antecedents of the proposed appointee to ensure his suitability for appointment under the Authority.

(8) "Every person appointed to a post under the Authority shall be on probation as per provisions thereto specified in the Recruitment Rules to be notified separately with the approval of the Central Government".

(9) The Chairman may devise and prescribe such forms, procedures, proformae, etc as may be necessary and appurtenant to sub regulations (5) (6) and (7) above.

- (a) The Chairman shall be the appointing authority for all posts carrying the scale of pay, the maximum of which is less than Rs. 13,500/- provided that all appointments made by him are against the posts sanctioned by the Central Government and shall be reported by him to the Executive Committee of the Authority and to the Central Government.
- (b) All appointments to the post carrying the scale of pay, the maximum of which is not less than Rs. 13,500/- shall be made by the Central Government as per the instructions issued in this behalf from time to time either through deputation of suitable officer from Central/State Governments or through direct recruitment.

- (c) The Chairman may devise such ways as he deems fit and necessary to assist him in the process of recruitment of suitable persons.
- (d) The Executive Committee may devise such ways and procedures as it deems fit to assist it in the recruitment of suitable persons. Where however no such procedures are prescribed, the Chairman shall take all steps in this behalf upto the stage of final selection by the Executive Committee and shall appoint the person selected by the Committee.
- (e) The Chairman or Committee may coopt or otherwise seek the assistance of outside experts to assist in the work of recruitment and selection and when such cooption is for the purpose of assistance at interviews an honorarium fixed in this regard with prior approval of the Central Government may be paid to the person so coopted.
- (f) The Authority may contract services, as deemed fit. No contract appointments of more than 6 months duration and/or having basic monthly remuneration of Rs. 1800/- or more shall be made without prior approval of the Central Government.
- (g) Notwithstanding anything contained in the Regulations, there will be no bar to any employee of the Authority being considered for any appointment on promotion or otherwise in the Authority in relaxation of any age bar, provided that:-
  - i) the employee possesses the other requisite qualifications, and
  - ii) the employee is considered suitable for the post.
- (h) Recruitment for various posts in the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority shall be made in accordance with the provisions of recruitment rules for such posts to be notified separately with the approval of the Central Government.

## CHAPTER VI

### FINANCE, BUDGET AND ACCOUNTS OF THE AUTHORITY

29. Budget Estimates:- (1) The Authority shall, in each financial year, prepare a budget for the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for the next financial year and shall submit it for sanction of the Central Government on or before such dates as may be specified from time to time by the Central Government.

- (2) No expenditure should be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government and the sanction for that expenditure by the Competent Authorities is received.
- (3) The budget shall include a statement of :-
- (a) the estimated opening balance;
  - (b) estimated receipts referred to in sub-section (i) of Section 16 of the Act;
  - (c) the estimated expenditure classified under various heads and sub-heads as the Central Government may from time to time direct;
- (4) Supplementary estimated expenditure, if any, shall be submitted for sanction of the Central Government in such form and on such dates as may be directed by it in this behalf.
- (5) Re-appropriation between heads and sub-heads of expenditure shall not be made save with the previous sanction of the Central Government.

## CHAPTER VII

### DELEGATION OF POWERS

30. Powers to sanction expenditure - (1) A Deputy Director/Manager or any other Officer of the Authority specified as Head of Office by the Chairman shall have power to sanction expenditure upto Rupees five hundred recurring and upto Rupees one thousand non-recurring relating to office contingencies, supplies and services on any single item subject to availability of the budget provisions relating to that item.

The Chairman may delegate his financial powers to the officers of the authority in pursuance of the Delegation of Financial Power Rules of the Central Government.

(2) An Assistance Director or officer of equivalent rank shall have power to sanction expenditure upto Rupees five hundred non-recurring for office contingencies, supplies and services on any single item at a time subject to availability of the budget provisions relating to that item.

31. Power to write off losses, enter into and execute contracts and lease deed

(1) The Chairman shall have power to write off as irrecoverable losses upto an amount of Rupees five hundred as irrecoverable and the Secretary shall have power to write off losses as irrecoverable upto an amount of two hundred and fifty rupees.

(2) The Authority may write off losses incurred by it up to rupees ten thousand, if the loss is due to theft, fraud and negligence in any single case and up to rupees twenty thousand in any single case, where such loss relates to public money, revenue or receipts, stores or other property held by or on behalf of the Authority, subject to observance of general conditions on the subject issued by the Central Government from time to time. The total amount in writing off losses in any year shall not exceed rupees one lakh. Writing off losses beyond this amount shall be done with the prior approval of the Central Government.

(3) The Chairman shall have power to enter into contracts which do not extend over a period of more than three years and also do not involve an expenditure of more than rupees fifty thousand. The Authority may enter into any contract for the discharge of its functions under the Act:

Provided that every agreement or contract for technical collaboration or consultation with firms or foreign Governments shall require the prior sanction of the Central Government.

(4) The Chairman shall have power to execute lease deeds and power of attorney

(5) The Secretary shall have power to execute such lease deeds and power of attorney the terms and conditions of which have been approved by the Chairman

(6) The Chairman shall be controlling officer in respect of his own travelling, daily allowances and of the members, officers and employees of the Authority.

Provided that the Chairman may appoint an officer of the Authority to be the Controlling Officer in respect of travelling daily allowance for an employee of the Authority, in the scale of pay, the minimum of which does not exceed Rs. 3050/- per month or its equivalent.

(7) All cheques and all orders for making deposit or investment or withdrawals of the sums or for the disposal in any other manner of the funds of the Authority shall:-

(a) If the cheques or orders are for an amount not exceeding Rs. 25000/-, be signed by the Secretary or, in his absence, any other officer nominated by the Chairman.

(b) If the Cheques or orders are for an amount exceeding Rs. 25000/-, be signed by the Secretary and an officer nominated by the Chairman and in the absence of the Secretary, such cheques shall be signed by such two officers nominated by the Chairman.

**32. Powers as to pay and allowances, leave and other conditions of Services of officers and other employees -** (1) Pay and allowance, leave and other conditions of services including age of superannuation and other facilities such as advance of pay, advances for the purchase of conveyance, construction of houses and the like, in respect of officers and employees appointed by the Authority shall, if no provision is made in these Regulations or otherwise, be regulated in accordance with such Rules and Regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the Central Government of the corresponding grades or status stationed at these places except for provisions relating to post retirement benefits such as pensions, General Provident Fund, medical reimbursement.

(2) Except as otherwise provided specifically, every employee of the Authority whose age of retirement is currently 58 years shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he/she attains the age of 60 years. However, employees whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 60 years.

(3) There shall be complete ban on extension in service of its officers and employees beyond the age of superannuation except in cases where exceptional circumstances exist justifying extension in service, it shall be granted with the prior sanction of the Central Government, on a case to case basis.

**33. Powers regarding deputation abroad -** The Authority shall not send any of its officer or any member of the Authority to places outside India without the previous sanction of the Government of India in the Ministry of Commerce.

S. M. ACHARYA, Jt. Secy.  
[No. Adv.-3/4/Exty/153/99]

---

Footnote :—The principal notification was issued vide F. No. Sec./AIR/02/93 dated the 18th January 1994.